can be formulated and suitable suggestion given. But where I disagree with him is when he says that the Janata Party has not indicated its educational policy. In fact, in my statement before you, Sir, I have indicated this policy and I have stated that we would lay more emphasis on the removal of illiteracy rather than on higher education. Of course, higher education is very important. But, at the same time, we notice that more than 200 million people are still illiterate. Therefore, this Government in pursuance of its declared policy will lay more emphasis on fundamental education.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: What about removal of corruption in universities?

श्री उपसभापति : अगला प्रश्न डा० लोकेश चन्द्र ।

इंस्टीट्यूट आफ अडवांस्ड स्टडीज, शिमला पर किया गया व्यय

*21. **डा० लोकेश चन्द्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1976–77 के वर्ष के दौरान इस्टीट्यूट आफ अडवांस्ड स्टडीज, शिमला पर विशेष कर विद्वानों और भवन के रख रखाव पर किये गये मासिक व्यय का ब्यौरा क्या है ?

†[**Expenditure incurred on the Institute of Advanced Studies, Simla**

*21. DR. LOKESH CHANDRA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state the details of the monthly expenditure incurred on the Institute of Advanced Studies, Simla, particularly on scholars and maintenance of the building during the year 1976-77?]

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट 100 अनुपत्र संख्या 2]

†[THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): A statement is laid on the Table of the House. (*See* Appendix C, Annexure No. 2)].

डा० लोकेश चन्द्र : माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो विवरण उन्होंने दिया है इसमें जो व्यय के अन्दर कुछ समस्यायें हैं उन का उल्लेख नहीं है, अगस्त 76 में संस्थान में आग लगाने का प्रयास किया गया था और उस आग लगाने की जांच जब पुलिस विभाग ने की और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें उन्होंने यह कहा कि यह आग इसलिये लगाई गई क्योंकि उस में 30–35 हजार रु० का गोलमाल है। यह प्रतिवेदन शासन को भी भेजा गया है क्या मंत्री महोदय इस पुलिस जांच के प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करने के लिये तैयार है या इस पर कोई टिप्पण करने को तैयार हैं ?

उप सभापति जी मेरा एक निवेदन और है । माननीय मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी होगी कि श्री सी० डी० देशमुख जी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज, शिमला के बारे में एक बहुत लम्बी रिपोर्ट लिखी थी । जहां तक मुझे जानकारी है इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । इस संस्थान के बारे में श्री सी० डी० देशमुख

†[ ] English translation.

ने अपनी जीवन कथा "दी कोर्स आफ माई लाइफ" के पृष्ठ 304 में संस्थान की असंतोषजनक कार्य पद्धति के बारे में लिखा है। मैं माननीय मंत्री जी यह जानना चाहता हूं कि डा० देशमुख समिति की जो रिपोर्ट है, क्या उस को मंत्री महोदय सदन में प्रस्तुत करेंगे ? इस के साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट पब्लिक एकाउन्टस कमेटी के सामने अथवा किसी अन्य संसदीय संस्था के सामने प्रस्तुत की गई या नहीं ?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: I am not aware of any police report. Certainly the matter will be looked into. As far as the report of the Committee under the chairmanship of Shri C. D. Deshmukh is concerned, I can say, by and large, that Committee has approved of the existence and utility of this institution. Although the institute had been in existence for three years by that time the Committee felt that the academic policy pursued and the programmes worked out by it have been sound and efficient. The Committee recommended that every effort should be made to allow the institute to continue the tradition it has been able to establish in a short span of existence. The institute has justified itself in a short period and it should be allowed to grow further without let or hindrance of any kind. It should be allowed to maintain its autonomy and its standard of academic freedom in the interest of healthy academic and intellectual tradition in our national life.

डा० लोकेश चन्द्र : माननीय मंत्री महोदय अभी जिस रिपोर्ट का उल्लेख किया है उस के संबंध में जानकारी समाचार पत्रों में भी आ चुकी है, पर उन्होंने इस के बारे में टाल मटोल कर दी मैं आशा करता हूं कि अब वे इस रिपोर्ट की ओर ध्यान देंगें क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि इंस्टीटयूट आफ एडवांस्ड स्टडीज सोसायटी की कोई बैठक नहीं हुई है। उस के संविधान के अनुसार इस की व्यवस्था इस सोसायटी के हाथ में नहीं होनी चाहिये। पर पिछले एक वर्ष से इस सोसायटी की भी बैठक नहीं हुई है जब कि संविधान के अनुसार प्रति वर्ष कम से कम चार बैठकें होनी चाहियें थी। इस के अन्दर जो नियुक्तियां हुई है वे भी शिक्षा मंत्रालय ने सीधे कर दी हैं और उन नियुक्तियों के अनुसार इस सोसायटी के जो अध्यक्ष है वे कभी भी शिमला में नहीं रहते है, सारे समय दिल्ली में ही रहते हैं जब कि संस्थान को चलाने का सारा दायित्व उन का होता है। इस के प्रशासन पर कम से कम 35 लाख रुपये खर्च होते है।

श्री उपसभापति : आप संक्षेप में प्रश्न पूछिये।

डा० लोकेश चन्द्र : मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि पिछले वर्षों में इस सोसायटी की एक भी बैठक नहीं हुई है ? अगर कोई बैठक हुई है तो वह भी बताने की कृपा करें। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि भविष्य में इस सोसायटी की बैठक कब बुलाने का विचार है ? मेरा एक छोटा सा प्रश्न यह भी है कि जो प्रबन्ध समिति, गवर्निंग बोडी सन 1973 में गठित की गई थी उस का पुनर्गठन पिछले चार साल से नही किया गया है। इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि कोई दूसरी प्रबन्ध समिति नियुक्त की गई है या नहीं ? इस प्रकार से इस व्यवस्था में जो अनियमितायें हो रही है क्या उन के संबंध में जांच करने के लिये आप कोई संसदीय समिति नियुक्त करने के लिये तैयार है या नहीं ?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: This institute is run by a registered society which has its own memorandum of association and rules and regulations. If there are irregularities in the working of the institute, certainly the Ministry will look into the matter.

श्री रबी राय : उपसभापति जी, जैसा मंत्री महोदय जानते हैं कि इस संस्थान पर एक साल में करीब 21 लाख रुपये से भी ज्यादा खर्च हुए हैं। ऐसी हालत में मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो शिमला में उच्चतम स्तर पर जांच होती है, इसका जन जीवन के साथ क्या ताल्लुक है? दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मान लीजिये कोई स्कालर अपनी अपनी मातृभाषा में निबन्ध लिखना चाहता है तो उस को इस की इजाजत होती है या नहीं।

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: As regards the utility of this institute, I have already read out extracts from the report submitted by the Committee under the chairmanship of Shri C. D. Deshmukh.

Then, Sir, with regard to the higher intellectual studies, actually the influence on the public may not be seen immediately. But, ultimately, the effect will permeate and reach the bottom rank of the society. So far as submission of materials in the mother-tongue is concerned, I understand that people who pursue studies in Hindi are also allowed in the Institute.

श्री रबी राय : उपसभापति महोदय, मेरा सवाल निबन्ध लिखने के बारे में नहीं था। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मेरा सवाल था थीसिस लिखने की इजाजत है या नहीं?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: I will require notice for that. It does not arise out of this question.

PROF. S. NURUL HASAN: It is not a degree-giving institution.

SHRI SHYAMLAL GUPTA: Sir, may I know from the honourable Minister one thing? So much money is being spent in the name of advanced studies. The former Minister is sitting there. Sir, during the last three years, I can say that nothing has been done. But payments have been made with the permission of the Minister and no advanced studies have been carried out and no theses have been submitted. May I know from the Minister whether any advanced studies were made and whether any thesis was submitted and approved or was made public? May I also ask whether the money that has been spent on these advanced studies was justified in any way? Sir, he may not be able to tell us. But the former Minister is sitting there and he may be able to tell us.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: Sir, before I answer this question, may I add to the answer which I have given to the honourable Member who spoke earlier? Material for publication may be submitted in Hindi and also in the other Indian languages.

SHRI SHYAMLAL GUPTA: Sir, my question was not whether it is in Hindi or in any other language. My question was different and it was specific.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: I said I was replying to the question of the honourable Member who spoke before Mr. Gupta. So far as the question of Mr. Shyamlal Gupta is concerned, I am not aware of these irregularities.

SHRI SHYAMLAL GUPTA: I think he will reply at least later.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Next question.

राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल

*22. **श्री नागेश्वर प्रसाद शाही :**
श्री नत्थी सिंह : †

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "जल" को एक राष्ट्रीय संसाधन घोषित करने का कोई निर्णय लिया है ; और

(ख) क्या सरकार भविष्य में अन्तर राज्यीय जल विवादों को रोकने, सभी राज्यों, विशेषकर उन राज्यों में जहां सिंचाई संसाधन नहीं है, जल के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने और बाढ़ों की समस्या को सुलझाने के लिये कोई राष्ट्रीय जल आयोग गठित करने का विचार रखती है ?

‡[**Water as a national resource**

22. SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI:
SHRI NATHI SINGH:†

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision to declare "water" as a national resource; and

(b) whether Government propose to set up a National Water Commission to prevent inter-state water disputes in future; ensure proper utilisation of water in all the States particularly in those States where there are no irrigational resources and to resolve the problem of floods?]

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) on behalf of the MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION: (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir.

(b) At present the State Governments virtually exercise full control on planning, development, regulation, distribution and control of the waters, flowing through their territories. However, most of the water resource is contributed by the inter-State rivers whose basins lie in more than one State. Differences with regard to use, distribution or control of the water of inter-State rivers sometimes do arise and efforts are being made to resolve them by negotiations either by the concerned States themselves or with the assistance of the Centre. Disputes which cannot be resolved by negotiations are being referred to the Tribunals to be constituted under the Inter-State Water Disputes Act, 1956. It is, however, increasingly felt that the Centre should play a more active role, particularly regarding allocation and regulation of waters of inter-State rivers and more expeditious modalities of resolving differences among the States need to be evolved. This would call for legislation by the Parliament. All these matters including appropriate institutional arrangements and new legislation are being vigorously studied by the Government.

§**कृषि और सिंचाई** मंत्री की ओर से **इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजु पटनायक)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Nathi Singh.

‡[ ] English translation.

§[ ] Hindi translation.